

08 $\frac{2}{21}$

पत्रावली प्रस्तुत । वकील पक्षकारान उपस्थित ।
वकील पक्षकारान द्वारा की गई बहस के बिन्दुओं
पर मनन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध
दस्तावेजों, प्रार्थना पत्र, जबाब प्रार्थना पत्र का
अवलोकन किया गया । प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों
का भी असम्मान अवलोकन किया गया ।

(क) ⇒ हस्तगत वाद पत्र/प्रार्थना पत्र में यह
स्वीकृत तथ्य है कि -

(i) प्रार्थी संख्या 1 व 2; अप्रार्थी संख्या 1 को
पूर्व पत्नी से उत्पन्न पुत्र एवं पुत्री हैं ।

(ii) अप्रार्थी संख्या 1 को जरिय वसीयत चक
प जीडी-ए के मु. न. 24/46 के किला न. 1 का
15 की कुल 15 बीघा खातेदारी कृषि भूमि अपने
दादा से प्राप्त हुई ।

(iii) अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त बिन्दु सं. (ii)

अनुसार जरिय वसीयत प्राप्त भूमि को अपनी
बाहिन पिरोजी देवी को जरिय दान पत्र दिनांक
01.02.2012 को हस्तान्तरित कर दिया ।



(iv) अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2

ने दिनांक 13.03.2012 को जरिय बैयनामा

(पृथक-पृथक) चक 27 एम.डी. का मु.न. 14 प.न. 205/9 की क्रमशः 4-365 है. व 1.960 है. भूमि खरोदी।

(ख) ⇒ हस्तगत वाद पत्र / प्रार्थना पत्र में उपर्युक्त स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त विवादात्मक बिन्दु निम्न लिखित हैं - (अथवा कानूनी बिन्दु)

(i) क्या किसी व्यक्ति को जरिअ वसीयत प्राप्त (अपने पिता से) भूमि उसके पुत्र के लिए पैतृक सम्पत्ति है?

(ii) क्या हस्तगत वाद पत्र / प्रार्थना पत्र में उल्लिखित दान पत्र दिनांक 01.02.2012 दानदाता द्वारा प्रतिकूल प्राप्त कर निष्पादित किया गया?

(iii) यदि दानदाता द्वारा दानपत्र दिनांक 01.02.2012 प्रतिकूल प्राप्त कर निष्पादित किया गया तो क्या उक्त प्रतिकूल के रूप में प्राप्त राशि से बैयनामा दिनांक 13.03.2012 द्वारा चक 27 एम.डी. के मु.न. 14 प.न. 205/9 की 25 बीघा कृषि भूमि क्रय की गई।

हस्तगत प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय को तीन बिन्दुओं क्रमशः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के संबंध में निर्णय करना है, जिसके संबंध में न्यायालय का विनिश्चय निम्न प्रकार से है -

(i) प्रथम दृष्टया प्रकरण -

जैसा कि खण्ड 'क' में उल्लिखित है, यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 की पूर्व पत्नी से उत्पन्न सन्ताने हैं। इसी खण्ड 'क' आदेशिका के खण्ड 'ख' से स्पष्ट है कि हस्तगत वाद पत्र में यह महत्वपूर्ण विवादात्मक बिन्दु है कि वाद में विवादित भूमि को पैतृक सम्पत्ति माना जावे अथवा नहीं। यह विनिश्चय करने के लिए खण्ड 'ख' में अंकित प्रत्येक बिन्दु पर कानूनी, दस्तावेजी अथवा मौखिक साद्यों की आवश्यकता होगी। यदि उक्तानुसार प्राप्त

साद्यों से अन्ततः यह साबित हो जाता है कि प्रश्नगत भूमि को प्रतिकूल प्राप्त करने के पश्चात् जरिद दानपत्र पैतृक भूमि को हस्तान्तरित कर उसी प्रतिकूल की राशि से क्रय किया गया है, तो प्राथमिकता का बिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के उक्त प्रश्नगत भूमि से जन्म से ही अधिकार निहित होगा। प्राथमिकता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2013 WLC (Raj.) UC 426 में भी माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान का मत है कि वाद में यदि विचारणीय विवादक हो तो अस्थायी व्यादेश निर्गत किया जाना चाहिए। अतः उक्त विवेचन के क्रम में प्रथम दृष्टया प्रकरण प्राथमिकता के पक्ष में सिद्ध होता है।

(ii) सुविधा का सन्तुलन -

जहाँ तक सुविधा के सन्तुलन का प्रश्न है, यदि दौराने वाद अप्राथमिकता द्वारा प्रश्नगत भूमि को विक्रय, रहन अथवा अन्यथा हस्तान्तरित कर दिया जाता है एवं अन्ततः वाद का निर्णय वादीगण के पक्ष में होता है तो असुविधा प्राथमिकता को होगी। इससे न केवल प्राथमिकता को असुविधा होगी, बल्कि यह कदम भविष्य में लिटिगेशन को बढ़ावा देने वाला भी होगा। इस तरह सुविधा का सन्तुलन भी प्राथमिकता के पक्ष में है।

(iii) अपूर्णनीय शक्ति -

यदि न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा का प्राथमिकता का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया जाता है एवं दौराने वाद अप्राथमिकता द्वारा दौराने वाद प्रश्नगत भूमि को रहन, बँय अथवा अन्यथा खुर्द-बुर्द कर दिया जाता है तथा अन्ततः वाद का निश्चय वादीगण के पक्ष में होता है, तो प्राथमिकता का अपूर्णनीय शक्ति होगी, क्योंकि प्राथमिकता अपनी संपत्ति के उपयोग एवं उपयोग से वंचित हो जायेगी। अतः अपूर्णनीय शक्ति का बिन्दु भी प्राथमिकता के पक्ष में सिद्ध है।

अतः उपर्युक्तानुसार न्यायालय की राय में प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध है, फलतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा. का. अ. स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

- : आदेश :-

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा. का. अ. स्वीकार कर इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा शतद्वारा जारी की जाती है कि प्रार्थीगण तहसील अनूपगढ़ के चक 21 एमडी के प.न. 205/09 मु.न. 14 के किला न. 1 ता 25 की कुल 6.325 हेक्टेयर कमांड कृषि भूमि को मूल बाढ़ के निस्तारण तक रखन, बेच अथवा अन्यथा हस्तान्तरित न करें एवं रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाकर रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाढ़ तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



08/2/21

(पवन कुमार)

उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़